Q.1) सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है।
2. कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध, जैसे कि इसके व्यय के समय ढाँचे, के साथ वितरित की जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोन
d) न 1 न 2

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
कथन 1 सही है . अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्राओं में भुगतान करना संभव है।
कथन 2 सही है. सीबीडीसी इस हद तक प्रोग्राम करने योग्य है कि मुद्रा को समाप्त किया जा सकता है, इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक निश्चित तिथि तक इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल युआन इस हद तक प्रोग्राम करने योग्य है कि मुद्रा को समाप्त होने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट तिथि तक इसे खर्च करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि डिजिटल मुद्राओं को पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर खर्च करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
Source: UPSC CSE PRE. 2023
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.2) ट्रेजरी बिल (T-Bills) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. टी-बिल शून्य-कूपन बांड हैं।
2. राज्य सरकारों के पास टी-बिल जारी करने का अधिकार नहीं है।
3. खुदरा निवेशक टी-बिल खरीदने के पात्र नहीं हैं।
4. बैंक अपने वैधानिक तरल अनुपात (एसएलआर) दायित्वों को पूरा करने के लिए टी-बिल का उपयोग कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल द
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
ट्रेजरी बिल या टी-बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक, मुद्रा बाजार ऋण उपकरण हैं और वर्तमान में तीन अवधियों, अर्थात् 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन में जारी किए जाते हैं।
कथन 1 सही है: ट्रेजरी बिल **शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं** और **कोई ब्याज नहीं देते हैं।** इसके बजाय, उन्हें **छूट पर जारी किया जाता है और** परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है।
कथन 2 सही है: भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है जबकि **राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं** , जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है।
कथन 3 गलत है: ट्रेजरी बिल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। **व्यक्ति (खुदरा निवेशक), ट्रस्ट, संस्थाएँ और बैंक** टी-बिल खरीद सकते हैं। लेकिन वे आमतौर पर वित्तीय संस्थानों के पास होते हैं। खुदरा निवेशक रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से टी-बिल की सदस्यता ले सकते हैं, जिसे

WWW.PDFNOTES.CO

आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया था।

कथन 4 सही है: बैंक **अपनी वैधानिक तरल अनुपात (एसएलआर) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टी-बिल का उपयोग कर सकते हैं।** वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है।

स्रोत: https://www.rbi.org.in/commonperson/english/scripts/FAQs.aspx?Id=711

https://www.business-standard.com/about/what-is-treasury-bills

https://rbiretaildirect.org.in/#/about_scheme

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.3) निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था में "लिक्विडिटी ट्रैप" की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

a) विदेशी निवेश के अचानक बहिर्वाह से वित्तीय बाजार में पूंजी तरलता की कमी हो जाती है।
b) केंद्रीय बैंकों की सख्त मौद्रिक नीति के कारण ऋण बाजार में अचानक ठहराव आ जाना।
c) एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहां बैंक की अधिकांश पूंजी अतरल परिसंपत्तियों में बंधी होती है, जो संभावित रूप से बैंक की विफलता के जोखिम में योगदान करती है।
d) ऐसी स्थिति जहां ब्याज दरें इतनी कम होती हैं कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी हो जाती है।

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जिसमें केंद्रीय बैंक उपलब्ध धन की कमी के कारण पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरणों के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में अपस्फीति या युद्ध जैसी प्रतिकूल स्थिति में, केंद्रीय बैंक विस्तारवादी नीति के हिस्से के रूप में ब्याज दर कम कर देता है। हालाँकि, लोग अपने निवेश से जुड़े बाज़ार जोखिम से बचने के लिए बाज़ार में निवेश करने के बजाय अपना पैसा बचाना पसंद करते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसी देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में केंद्रीय बैंक की विस्तारवादी नीति विफल हो जाती है।

विकल्प a गलत है: कैपिटल फ्लाइट एक ऐसी घटना को संदर्भित करती है जहां निवेशक अपनी वित्तीय संपत्तियों को बेचकर बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था से पूंजी निकालते हैं। विदेशी निवेश के इस तरह अचानक बाहर जाने से वित्तीय बाजार में पूंजी तरलता की कमी हो जाती है।

विकल्प b गलत है: क्रेडिट संकट उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वित्तीय संस्थानों से उधारकर्ताओं को ऋण या ऋण की उपलब्धता में अचानक कमी आ जाती है। आरबीआई द्वारा अत्यधिक विनियमन से बैंकों की ऋण सृजन करने की क्षमता बाधित होती है जिससे ऋण संकट की स्थिति पैदा होती है।

विकल्प c गलत है: तरलता जोखिम किसी संस्थान की संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता (चाहे वास्तविक या कथित) से उत्पन्न होने वाली वित्तीय स्थिति या सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए जोखिम है।

जब बैंक की पूंजी अतरल परिसंपत्तियों में बंधी होती है, तो इससे बैंक की विफलता के जोखिम में योगदान देने वाले विशेष बैंक की तरलता जोखिम पैदा हो जाती है।

विकल्प d सही है: लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जब **कम ब्याज वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी होती है।**

Source: https://economictimes.indiatimes.com/definition/liquidity-trap

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/what-is-capital-flight-in-economics/article19032960.ece- Capital flight

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0025.pdf- Credit crunch

https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/topics/liquidity_risk.htm - Liquidity risk

S Subject:) Economy Subtopic:) Monetary Policy

WWW.PDFNOTES.CO

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि के दौरान बांड प्रतिफल घट जाती है।
कथन II: आर्थिक मंदी के दौरान, निवेशक इक्विटी शेयर बेचते हैं और बांड खरीदना पसंद करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I के लिए सही व्याख्या है।
b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I के लिए सही व्याख्या नहीं है।
c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
बांड एक प्रकार का ऋण है जो किसी निवेशक द्वारा किसी उधारकर्ता - किसी कंपनी या संस्था - को नियमित ब्याज भुगतान के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है।
बांड, ब्याज भुगतान के माध्यम से विश्वसनीय रिटर्न प्रदान करते हैं जबकि स्टॉक निवेशकों को कोई गारंटीकृत आय प्रदान नहीं करते हैं।
बांड मूल्य बांड का वर्तमान बाजार मूल्य है। बॉन्ड प्रतिफल उस रिटर्न का प्रतिनिधित्व करती है जो एक निवेशक को बॉन्ड रखने से प्राप्त होता है। बॉन्ड प्रतिफल और बॉन्ड की कीमत के बीच का संबंध विपरीत रूप से संबंधित है। दोनों के बीच संबंध की गणितीय अभिव्यक्ति है:
प्रतिफल = (कूपन/बांड का बाजार मूल्य) X 100
मंदी से तात्पर्य किसी देश भर में आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट से है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश में आर्थिक विकास दर में कमी आती है।
कथन I सही है: मंदी के **कारण बांड प्रतिफल में गिरावट आती है** । ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनिश्चितता और नकारात्मक विकास के दौर में, लोग अधिक जोखिम वाले कंपनी शेयरों की तुलना में बांड में अपने निवेश को प्राथमिकता देंगे क्योंकि यह गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करता है। इससे **बांड की मांग बढ़ जाती है, और इससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे बांड की प्रतिफल कम हो जाती है।**
कथन II सही है: मंदी के दौरान, निवेशक अक्सर अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए **सुरक्षित निवेश विकल्प तलाशते हैं।** स्टॉक जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की तुलना में बांड को अधिक सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि बांड ब्याज भुगतान के रूप में समय पर रिटर्न और परिपक्वता अवधि के बाद समान मूल राशि प्रदान करते हैं।
कथन II, कथन I की सही व्याख्या है, क्योंकि मंदी के दौरान, लोग बांड को सुरक्षित निवेश अवसर मानते हैं और स्टॉक जैसे अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में बांड को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार, मंदी के दौरान बांड की बढ़ती मांग से बांड की प्रतिफल कम हो जाती है।
मंदी निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित रखते हैं स्टॉक के मुकाबले बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है बॉन्ड की मांग बढ़ती है बॉन्ड प्रतिफल घटती है
Source: https://www.southindianbank.com/userfiles/file/sef_352.pdf
https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/us-bond-yield-why-rising-explained-8997263/
Subject:) Economy
Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.5) निम्नलिखित में से कौन सा कथन कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द 'ग्रीडफ्लेशन (Greedflation)' का सही वर्णन करता है?
a) यह अत्यधिक उपभोक्ता खर्च के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि का संकेत देता है।
b) यह एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं जिससे आपूर्ति में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी होती है।
c) यह प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के कारण लोगों के जीवनयापन की लागत में वृद्धि को संदर्भित करता है।
d) यह कॉर्पोरेट लालच और मूल्य हेरफेर से प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रतीक है।

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है ।

'ग्रीडफ्लेशन' एक ऐसी आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति की दर कॉर्पोरेट 'ग्रीड' से प्रेरित होती है। इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले मानक आर्थिक कारकों के बजाय कॉर्पोरेट लालच ऊंची कीमतों में योगदान देता है।

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 29

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Greedflation

Q.6) 'अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बांड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. AT1 बांड में आमतौर पर एक परिभाषित परिपक्वता अवधि का अभाव होता है।
2. AT1 बांड बैंकों के मुख्य पूंजी भंडार द्वारा समर्थित हैं।
3. AT1 बांड का द्वितीयक बाज़ारों में कारोबार नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

अतिरिक्त टियर 1 **(एटी1) बांड 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अनिश्चित बैंकों के सरकारी वित्त पोषित बेलआउट की आवश्यकता को रोकने के लिए बनाए गए "आकस्मिक-परिवर्तनीय" बांड का एक रूप हैं।** हालांकि उच्च संभावित रिटर्न का वादा करते हुए, अगर बैंक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे नुकसान का खामियाजा भुगतते हैं।

कथन 1 सही है : **AT1 बांड स्थायी साधन हैं जिनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं है** । इनमें कॉल विकल्प शामिल हैं जो बैंकों को एक निश्चित अवधि, आमतौर पर पांच या 10 वर्षों के बाद उन्हें भुनाने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, बैंक इस कॉल विकल्प का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं हैं और अनिश्चित काल तक केवल ब्याज का भुगतान करना चुन सकते हैं।

कथन 2 गलत है: अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बांड असुरक्षित बांड हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी बैंक पूंजी द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके विपरीत, सुरक्षित बांड संपार्श्विक द्वारा समर्थित होते हैं, और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बांडधारकों के पास अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर दावा होता है।

कथन 3 गलत है: AT1 बांड का द्वितीयक बाजारों में कारोबार किया जा सकता है, जिससे AT1 बांडधारकों को धन जुटाने के लिए उन्हें शेयर बाजार में अन्य निवेशकों को बेचने की अनुमति मिलती है।

Source: https://www.weforum.org/agenda/2023/03/at1-bonds-banking-financial/

https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/financial-services/explainer-what-are-at-1-bonds-and-how-risky-are-they/99159550

https://indianexpress.com/article/explained/explained-climate/holi-becoming-warmer-study-9229260/

https://www.livemint.com/industry/banking/did-rbi-change-its-mind-on-yes-bank-s-at-1-bonds-11641232192570.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mint_top_morning_newsletter

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

WWW.PDFNOTES.CO

Q.7) भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एमपीसी बेंचमार्क ब्याज दरें तय करने के लिए जिम्मेदार है।
2. मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णय केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी होते हैं।
3. एक वर्ष में एमपीसी की कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 में संशोधन करके की गई थी। समिति निम्नलिखित सदस्यों से बनी है:
(a) बैंक का गवर्नर **पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।**
(b) बैंक का डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार, पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है।
(c) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में भी कार्य करता है।
(d) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
कथन 1 सही है: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अनुसार, **मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है** । यह नीति दर, केंद्रीय बैंक की एक महत्वपूर्ण उधार दर, अर्थव्यवस्था में अन्य सभी अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करती है, जिससे आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के स्तर पर असर पड़ता है।
कथन 2 सही है: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB **में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णय केंद्रीय बैंक के लिए बाध्यकारी हैं।** इसलिए, एमपीसी के निर्णय केंद्रीय बैंक के कार्यों पर कानूनी अधिकार रखते हैं।
कथन 3 सही है: बैंक एक वर्ष में मौद्रिक नीति समिति की कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा। एक वर्ष के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यक्रम उस वर्ष की पहली बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।
Source: https://m.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752#:~:text=meeting%20of%20the-,MPC,-is%20four%20members
http://www.arthapedia.in/index.php/Policy_Rate#:~:text=other%20short%20term-,interest,-rates%20in%20the
https://indianexpress.com/article/explained/explained-climate/holi-becoming-warmer-study-9229260/
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.8) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे सुरक्षित वित्तीय साधन हैं।
2. इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है।
3. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की सदस्यता ले सकते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) निगमों द्वारा प्राप्य खातों और इन्वेंट्री लागत जैसी तत्काल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं। वे असुरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास कोई संपार्श्विक समर्थन नहीं है। सीपी आम तौर पर ऋण की असुरक्षित प्रकृति के कारण उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो निवेशकों के लिए उच्च जोखिम का संकेत देता है।

कथन 1 गलत है: सीपी असुरक्षित होते हैं, वे किसी भी प्रकार की सुरक्षा या संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं हैं। जारीकर्ता कंपनी की क्रेडिट पात्रता निवेशकों के लिए उनके निवेश के पुनर्भुगतान के संबंध में प्राथमिक आश्वासन है।

कथन 2 गलत है: सीपी को अल्पकालिक उपकरण माना जाता है जिसकी परिपक्वता अवधि आमतौर पर 7 दिन से लेकर 364 दिन (या एक वर्ष से कम) तक होती है। इनका उपयोग अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, दीर्घकालिक दायित्वों के लिए नहीं।

कथन 3 सही है: अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की सदस्यता में भाग लेने के पात्र हैं। सीपी को एनआरआई और एफआईआई सहित विभिन्न प्रकार के निवेशकों द्वारा रखा जा सकता है, जो बाजार में विविध निवेशक आधार और तरलता की अनुमति देता है।

Source: Indian Economy by Ramesh Singh,

Ch: 11 - Financial markets

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.9) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UPI के माध्यम से किए गए लेनदेन किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तनीय हैं।
2. यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की जाने वाली धनराशि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। यूपीआई कई बैंक खातों को एक ही यूपीआई सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन में एक साथ लाता है, किसी भी भाग लेने वाले बैंक की कई सुविधाओं को विलय करता है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों के लिए निर्बाध फंड ट्रांसफर सक्षम होता है।

कथन 1 गलत है: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने गलत या अनधिकृत लेनदेन को सुधारने के लिए **"यूपीआई ऑटो-रिवर्सल" प्रणाली शुरू की है।** यदि कोई व्यक्ति गलत प्राप्तकर्ता को पैसा भेजता है या अनधिकृत लेनदेन का सामना करता है , तो वे अपने बैंक या यूपीआई सेवा प्रदाता से संपर्क करके , रिवर्सल में तेजी लाने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करके **रिवर्सल प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।**

कथन 2 सही है: हस्तांतरित की जा सकने वाली धनराशि की कोई निचली सीमा नहीं है, यूपीआई ने ब्रिक-एण्ड-मोर्टार स्टोरों के लिए छोटे भुगतान स्वीकार करना आसान बना दिया है।

Source: https://razorpay.com/blog/what-is-upi-and-how-it-works/#What_is_Unified_Payments_Interface_UPI

https://www.business-standard.com/industry/news/fintechs-raise-upi-payment-charging-concerns-with-fm-nirmala-sitharaman-124022900942_1.html

WWW.PDFNOTES.CO

https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/how-to-reverse-upi-transactions-on-phonepe-paytm-google-pay-and-other-upi-apps/articleshow/103574453.cms
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.10) वह गोंडवाना की शासक रानी और मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थी। उन्होंने मुगल आक्रमण के खतरे के खिलाफ बहादुरी से अपने साम्राज्य की रक्षा की और माना जाता है कि उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को खंजर से मार डाला था।
उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है?
a) रानी दुर्गावती
b) रानी लक्ष्मीबाई
c) रानी कर्णावती
d) रानी चाँद बीबी

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है ।
हाल ही में मध्य प्रदेश में **रानी दुर्गावती** गौरव यात्रा आयोजित की गई थी. रानी दुर्गावती की विरासत अक्सर उनके राज्य की वीरतापूर्ण रक्षा और अपने लोगों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है।
रानी दुर्गावती (1524-1564) मुग़ल सम्राट अकबर (1542-1605) की समकालीन थीं । वह **1550-1564 के बीच गोंडवाना की** शासक रानी थीं और यह साम्राज्य **गोंड जनजाति के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है** । उन्हें मुख्य रूप से **मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए याद किया जाता है** जब उनके राज्य पर मुगल जनरल **अब्दुल माजिद आसफ खान ने हमला किया था** । जब यह स्पष्ट हो गया कि मुगल सेना राज्य पर कब्ज़ा कर लेगी, तो माना जाता है कि उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय **खुद को खंजर से मार लिया था ।**
Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 60
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) Rani Durgavati

Q.11) परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चूँकि इक्विटी के बदले बांड का आदान-प्रदान करने का विकल्प होता है, परिवर्तनीय बांड कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
2. इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प बॉन्डधारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के लिए इंडेक्सेशन की एक डिग्री प्रदान करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न 1 न 2

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
कथन 1 सही है : परिवर्तनीय बांड, बांड को सामान्य स्टॉक में बदलने के विकल्प के मूल्य के बदले में **कम कूपन दर या रिटर्न की दर की पेशकश करते हैं।** निवेशक आमतौर पर परिवर्तनीय बांड पर इसकी रूपांतरण सुविधा के कारण, अन्यथा समान नियमित बांड पर कूपन दर की तुलना में कम कूपन दर स्वीकार करेंगे। यह जारीकर्ता को ब्याज खर्च बचाने में सक्षम बनाता है, जो बड़े बांड मुद्दे के मामले में पर्याप्त हो सकता है।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 2 सही है : इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प **बॉन्डधारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के लिए इंडेक्सेशन की एक डिग्री प्रदान करता है** क्योंकि इक्विटी की कीमतें दिए गए ब्याज से व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं और उसमें अंतर को मुद्रास्फीति के लिए बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Source: UPSC CSE PRE. 2022

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.12) वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) एक स्वायत्त निकाय है जिसने बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का स्थान लिया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर FSIB के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
3. एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) एक नियामक निकाय है जिसका काम वित्तीय संस्थानों की निगरानी करना है ताकि वे कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।

कथन 1 सही है: एफएसआईबी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, और इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के प्रशासन को बढ़ाने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की जगह ले ली है।

कथन 2 गलत है: एफएसआईबी की अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती है (आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में नहीं)।

कथन 3 सही है: एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (एनईसी) के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।

Source: https://www.thehindubusinessline.com/blexplainer/from-banks-board-bureauto-financial-services-institutions-bureau-all-that-you-need-to-know/article65653269.ece?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en&cc=IN&safesearch=moderate

Subject:) Economy

Subtopic:) Monetary Policy

Q.13) नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीआरआर फंड आरबीआई के पास रखे जाते हैं, जबकि एसएलआर फंड बैंकों के पास ही रखे जाते हैं।
2. सीआरआर आरबीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य है, जबकि एसएलआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अनिवार्य है।
3. बैंक एसएलआर के रूप में रखे गए फंड से ब्याज कमाते हैं, लेकिन सीआरआर के रूप में रखे गए फंड से नहीं।
4. एसएलआर पर एक वैधानिक ऊपरी सीमा है, लेकिन सीआरआर पर नहीं।

WWW.PDFNOTES.CO

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बैंक जमा का वह हिस्सा है जिसे केंद्रीय बैंक के पास रखना आवश्यक है, जिससे उधार देने के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है और धन आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रभावित होती है।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बैंकों को तरलता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नकदी, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों में अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखने का आदेश देता है।
कथन 1 सही है: नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के लिए बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास नकदी में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बैंक के भीतर ही तरल संपत्तियों में उनकी जमा राशि।
कथन 2 सही है: सीआरआर आरबीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य है, जो आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली में तरलता को विनियमित करने की अनुमति देता है। **एसएलआर को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अनिवार्य किया गया है,** जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति का बफर बनाए रखें।
कथन 3 सही है: बैंक आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखे गए नकद आरक्षित पर कोई ब्याज नहीं कमाते हैं । सीआरआर के विपरीत, एसएलआर विंडो के तहत निवेश किया गया पैसा बैंकों के लिए कुछ ब्याज अर्जित करता है। लेकिन वे ऋण देने के प्रयोजनों के लिए इस निधि का उपयोग नहीं कर सकते। सीआरआर में केवल नकद भंडार शामिल है, लेकिन एसएलआर में सोना, बांड और प्रतिभूतियां जैसी तरल संपत्तियां शामिल हैं।
कथन 4 सही है: एसएलआर की बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक/कानूनी ऊपरी सीमा (40%) है । हालाँकि, सीआरआर की कोई कानूनी ऊपरी सीमा नहीं है; आरबीआई सीआरआर दर निर्धारित कर सकता है।
Source: https://www.rbi.org.in/commonperson/english/Scripts/Notification.aspx?Id=1476
&
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12131&Mode=0
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/what-are-crr-slr-with-respect-to-banks/articleshow/72979135.cms?from=mdr
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.14) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
2. वाणिज्यिक पत्र (सीपी)
3. नकद प्रबंधन विधेयक (सीएमबी)
4. ट्रेजरी बिल (टी-बिल)
उपरोक्त में से कितने भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

विकल्प 1 सही है: जमा प्रमाणपत्र एक सावधि जमा है, जो बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला एक वित्तीय उत्पाद है , जो ग्राहक को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एकमुश्त जमा राशि को बिना प्रभावित करने के बदले में ब्याज दर प्रीमियम प्रदान करता है।

विकल्प 2 गलत है: वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक ऋण साधन है जो बड़े निगमों द्वारा अल्पकालिक देनदारियों को वित्तपोषित करने के लिए जारी किया जाता है। यह बैंकों द्वारा नहीं बल्कि कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है।

अस्थायी नकदी प्रवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए **सरकार द्वारा जारी की गई अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं ।** एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता वाली **अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं ।** इन्हें बैंकों द्वारा जारी नहीं किया जाता बल्कि सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है।

Source: Indian Economy by Ramesh Singh,

Ch: 11 - Financial markets

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.15) 'आर्टेमिस समझौते' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है।
3. इसका उद्देश्य भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है ।

कथन 1 सही है: भारत हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में शांतिपूर्ण सहयोग से संबंधित आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है।

कथन 2 गलत है: आर्टेमिस समझौता **कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है** । यह अमेरिका और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य देशों के बीच एक गैर-बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है।

कथन 3 सही है: यह सत्य है कि **आर्टेमिस समझौते का** उद्देश्य **भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।** इसका अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे तक अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है।

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 47

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Artemis Accords

Q.16) लघु वित्त बैंकों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्हें न्यूनतम पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
2. उन्हें अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में विस्तारित करना आवश्यक है।
3. उनके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 75% हिस्सा 25 लाख तक के ऋण और अग्रिम का होना चाहिए।

WWW.PDFNOTES.CO

उपरोक्त में से कितने कथन **गलत हैं** ?

a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है
(1) मुख्य रूप से आबादी के असेवित और अल्पसेवित वर्गों के लिए बचत वाहनों का प्रावधान, और
(2) उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत वाले संचालन के माध्यम से लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण की आपूर्ति।

कथन 1 ग़लत है . अंतर्निहित जोखिम के कारण, छोटे वित्त बैंकों को समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी उच्च प्रतिशत के अधीन निरंतर आधार पर **अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) का 15% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है।**

कथन 2 सही है . छोटे वित्त बैंकों को अपने **समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75%** आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विस्तारित करना आवश्यक है।

कथन 3 ग़लत है । छोटे वित्त बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में 25 लाख तक के ऋण **का कम से कम 50% (75% नहीं) होना चाहिए।**

Source: https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3764
Indian Economy by Vivek Singh Chapter 2
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.17) यदि रिवर्स रेपो दर में 100 आधार अंकों की वृद्धि की जाती है, तो क्या होने की सबसे अधिक संभावना है?

a) बैंक अपने अतिरिक्त भंडार को केंद्रीय बैंक के पास जमा करने में अधिक इच्छुक महसूस कर सकते हैं।
b) अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
c) जनता के लिए कर्ज सस्ता हो जायेगा।
d) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति स्थिर होगी।

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक) देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग देश में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

कथन a सही है. बैंक अपने अतिरिक्त भंडार को केंद्रीय बैंक के पास जमा करने में **अधिक रुचि महसूस कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के कारण वे** जमा पर **अधिक ब्याज कमा सकते हैं ।**

कथन b ग़लत है । अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति **घटती है, बढ़ती नहीं** । ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई बैंक आरबीआई के पास अपना धन जमा करके रिवर्स रेपो दर के बराबर दर पर ब्याज अर्जित कर सकता है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है, तो यह मुद्रा बाजार में उधार दिए गए धन के लिए उच्च ब्याज दर वसूलने की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो गई।

कथन c ग़लत है । जनता के लिए ऋण **महंगे हो जाएंगे और सस्ते नहीं होंगे क्योंकि आरबीआई के पास अतिरिक्त धन रखकर अधिक जोखिम-मुक्त रिटर्न अर्जित करने के विकल्पों की उपलब्धता के कारण बैंक अधिक ब्याज दर वसूलने के इच्छुक हैं।**

WWW.PDFNOTES.CO

कथन d ग़लत है । हालाँकि मुद्रा आपूर्ति में कमी संभावित रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह कोई गारंटीकृत परिणाम नहीं है। मुद्रास्फीति विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, और रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी का प्रभाव विशिष्ट आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

Source: https://economictimes.indiatimes.com/definition/reverse-repo-rate

Indian Economy by Vivek Singh

Subject:) Economy

Subtopic:) Monetary Policy

Q.18) वित्तीय साधनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कारोबार शेयर बाजार में नियमित स्टॉक की तरह किया जाता है जबकि म्यूचुअल फंड का कारोबार बाजार के दिन के अंत में किया जाता है।
2. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आम तौर पर म्यूचुअल फंड योजनाओं की तुलना में निवेशकों के लिए अधिक कर कुशल माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न 1 न 2

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

कथन 1 सही है . ईटीएफ का शेयर बाजार में नियमित शेयरों की तरह ही आदान-प्रदान किया जाता है जो **उनकी तरलता को बढ़ाता है** जबकि म्यूचुअल फंड का कारोबार केवल एनएवी मूल्य पर बाजार के दिन के अंत में किया जाता है (शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) एक फंड के प्रति-शेयर आंतरिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।)

कथन 2 सही है . ईटीएफ में आम तौर पर म्यूचुअल फंड योजनाओं की तुलना में अधिक दैनिक तरलता और कम शुल्क होता है, जो उन्हें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। ईटीएफ को आम तौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक कर-कुशल माना जाता है, इस **तथ्य के कारण कि उनमें आम तौर पर कम पूंजीगत लाभ वितरण होता है।**

Source: https://indianexpress.com/article/explained/pm-modi-ed-west-bengal-cash-attach-procedure-9240001/

https://groww.in/blog/what-is-the-difference-between-etf-and-mutual-fund

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.19) मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सुविधा सभी अनुसूचित बैंकों के लिए उपलब्ध है।
2. एमएसएफ प्रावधान के तहत उधार लेने के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।
3. एमएसएफ दर आम तौर पर रेपो रेट से अधिक होती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

जमा और ऋण पोर्टफोलियो के बेमेल होने से उत्पन्न वित्तीय अंतराल के कारण बैंकों को अक्सर तरलता की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कमी लंबे समय तक नहीं रहती है और ऐसी आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए बैंक एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत त्वरित धन के लिए आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं।

कथन 1 सही है. एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक अल्पकालिक उधार योजना है जो **अनुसूचित बैंकों को** गंभीर नकदी की कमी के मामले में भारत के केंद्रीय बैंक से रातोंरात धन प्राप्त करने की सुविधा देती है।

कथन 2 ग़लत है . एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा के तहत, बैंक एसएलआर रिजर्व से जी-सिक्योरिटी का 2% आरबीआई को **संपार्श्विक के रूप में पेश कर सकते हैं** और आरबीआई से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, एमएसएफ सुविधा का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक होना आवश्यक है।

कथन 3 सही है . अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में एक सीमा (एसएलआर का 2%) तक ब्याज की दंडात्मक दर पर रिज़र्व बैंक से अतिरिक्त धनराशि उधार ले सकते हैं **जो रेपो दर (एमएसएफ दर =) से ऊपर है। रेपो दर + दंड दर)** । इसलिए, एमएसएफ या सीमांत स्थायी सुविधा दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है।

Source: Indian Economy by Vivek Singh.

Subject:) Economy

Subtopic:) Monetary Policy

Q.20) निपाह वायरस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक ज़ूनोटिक बीमारी है।
2. फिलहाल इस बीमारी के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न 1 न 2

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

कथन 1 सही है: निपाह वायरस संक्रमण एक ज़ूनोटिक बीमारी है जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। निपाह वायरस के लिए मेजबान पशु भंडार फल चमगादड़ है, जिसे आमतौर पर फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है।

कथन 2 सही है: वर्तमान में, मनुष्यों या जानवरों के लिए इस वायरल बीमारी का कोई **इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है।**

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 51

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Nipah virus

Q.21) निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है?

a) सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान
b) बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना
c) बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना
d) बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए धन का निर्माण

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

घाटे के वित्तपोषण का अर्थ है घाटे को पूरा करने के लिए धन उत्पन्न करना जो राजस्व पर व्यय की अधिकता के परिणामस्वरूप होता है। इस अंतर को बांड की बिक्री या **नए पैसे छापकर जनता से उधार लेकर पूरा किया जा रहा है।**

पैसा छापकर सरकारी व्यय से आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में निजी मांग बढ़ती है। इस प्रकार, यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है । मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि स्वस्थ है क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। लेकिन अगर सरकार समय रहते इसे नहीं रोकती है, तो **बाजार में अधिक पैसा भर जाता है और उच्च मुद्रास्फीति पैदा होती है** । और चूंकि मुद्रास्फीति का खुलासा देरी से होता है, इसलिए अक्सर सरकारों को यह एहसास होने में बहुत देर हो जाती है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा उधार ले लिया है **। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च सरकारी ऋण व्यापक आर्थिक अस्थिरता के लिए आधार प्रदान करते हैं।**

स्रोत: यूपीएससी सीएसई प्री। 2021

विषय:) अर्थव्यवस्था

उपविषय:) मौद्रिक नीति

Q.22) अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. WMA के लिए ली जाने वाली ब्याज दर रेपो दर के समान है।
2. WMA की सीमाएँ FRBM अधिनियम द्वारा तय की जाती हैं।
3. WMA का उपयोग सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी ऋण सुविधाएं देता है। इस अस्थायी ऋण सुविधा को वेज एंड मीन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) कहा जाता है।

कथन 1 सही है . वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज (डब्ल्यूएमए) आरबीआई से 90 दिनों के लिए ऋण सुविधा है और डब्ल्यूएमए के लिए ब्याज दर अप्रैल 2021 से रेपो दर पर ली जाती है।

कथन 2 ग़लत है . अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमाएं आरबीआई और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं और एफआरबीएम अधिनियम के तहत तय नहीं की जाती हैं।

कथन 3 ग़लत है । अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का उपयोग न तो आम तौर पर और न ही विशेष रूप से राजकोषीय घाटे को निधि देने के लिए किया जाता है। यह सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के बीच विसंगति को पूरा करने के लिए एक अस्थायी ऋण सुविधा है।

Source: Indian Economy by Vivek Singh.

https://www.rbi.org.in/commonperson/english/scripts/PressReleases.aspx?Id=3296

Subject:) Economy

Subtopic:) Monetary Policy

Q.23) भारत में वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: बैंकों, एनबीएफसी के विपरीत:

1. मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते.
2. स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकता।

WWW.PDFNOTES.CO

3. जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा के अंतर्गत कवर नहीं हैं
4. सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं कर सकते।
बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर के बारे में ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 1956/2013** के तहत एक पंजीकृत कंपनी है, जो ऋण प्रदान करने, सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी शेयर / बॉन्ड / प्रतिभूतियों को खरीदने, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा और चिट व्यवसाय जैसी गतिविधियों में शामिल है। हालाँकि, इसमें मुख्य रूप से कृषि या औद्योगिक गतिविधियों, व्यापारिक वस्तुओं (प्रतिभूतियों को छोड़कर), सेवाएँ प्रदान करने या अचल संपत्ति में काम करने वाली कंपनियाँ शामिल नहीं हैं।
कथन 1 सही है: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मांग जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है , जो कि चालू या बचत खातों की तरह मांग पर धनराशि निकाली जा सकती है, बैंकों के विपरीत जिन्हें ऐसी जमा स्वीकार करने की अनुमति है। जबकि एनबीएफसी सावधि जमा और आवर्ती जमा सहित विभिन्न प्रकार की जमा स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें मांग जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। जो एनबीएफसी अन्य प्रकार की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं उन्हें जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कहा जाता है
कथन 2 सही है: एनबीएफसी अपनी सेवाओं के हिस्से के रूप में स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं, बैंकों के विपरीत जो विभिन्न लेनदेन के लिए खाताधारकों को चेक जारी कर सकते हैं। जबकि एनबीएफसी ऋण और क्रेडिट सुविधाओं सहित वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वे भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं और इस प्रकार, उन्हें स्वयं पर आहरित चेक जारी करने की अनुमति नहीं है।
कथन 3 सही है: भारत में **डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान किया जाने वाला डिपॉजिट बीमा** विशेष रूप से बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नहीं** । यह अंतर बैंकों और एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले विभिन्न नियामक ढांचे से उत्पन्न होता है, बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जमा बीमा प्रदान करना अनिवार्य है, जबकि एनबीएफसी, जो मुख्य रूप से ऋण देने और अन्य वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं, जमा बीमा योजना के तहत कवर नहीं हैं। .
कथन 4 गलत है: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आम तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों को हासिल करने की अनुमति दी जाती है, जो सरकार द्वारा उधार के रूप में जारी की जाती हैं, नियामक दिशानिर्देशों के अधीन, बैंकों के पास भी ऐसी प्रतिभूतियों को हासिल करने का अधिकार है। एनबीएफसी और बैंकों को मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां हासिल करने की अनुमति है क्योंकि इन प्रतिभूतियों को सुरक्षित और तरल निवेश माना जाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार के ऋण द्वारा समर्थित होती हैं, जिससे वे डिफ़ॉल्ट के मामले में लगभग जोखिम-मुक्त हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति माना जाता है और वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ज्ञान का आधार: **जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ने** जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान किए गए जमा बीमा की स्थापना की। **DICGC** भारत में विदेशी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को जमा बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक) भी शामिल हैं जहां सहकारी समिति अधिनियम नियामक कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिकार देता है। DICGC की जमा बीमा योजना में सभी सहकारी बैंक शामिल हैं । DICGC बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी जमाओं का बीमा करता है। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक बीमा किया जाता है। वही अधिकार और क्षमता.
Source: https://agloc.org/pdf/RBI%20FAQs%20NBFCs%2010-04-15.pdf
https://www.rbi.org.in/commonperson/english/scripts/FAQs.aspx?Id=1167

WWW.PDFNOTES.CO

https://www.livemint.com/market/mark-to-market/lazy-banks-or-flaky-borrowers-11665335305722.html
https://www.dicgc.org.in/FD_A-GuideToDepositInsurance.html
https://www.aubank.in/dicgc-deposit-insurance-and-credit-guarantee-corporation#:~:text=The%20DICGC%20insures%20all%20deposits,the%20same%20right%20and%20capacity.
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.24) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा "फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG)' प्रणाली शब्द के अर्थ का सही वर्णन करता है?
a) उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चूक के लिए वित्तीय संस्थानों की प्रतिपूर्ति के लिए तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारंटी।
b) सड़क परियोजनाओं के परियोजना डेवलपर्स को वित्तीय घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया एक आश्वासन।
c) एक ऐसी व्यवस्था जो बैंकों को डिफ़ॉल्ट की पहली घटना के मामले में उधारकर्ताओं की संपार्श्विक (collateral) बेचने में सक्षम बनाती है।
d) ऋण चूक के लिए दंड को अस्थायी रूप से माफ करने के लिए उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच एक समझौता।

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
विकल्प a सही है: "फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) तीसरे पक्ष और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच एक वित्तीय व्यवस्था प्रदान करती है। एफएलडीजी में, तीसरे पक्ष **वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋण में डिफ़ॉल्ट के** एक निश्चित प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति करते हैं ।
ज्ञान का आधार: **वित्तीय संस्थानों द्वारा नियुक्त तीसरे पक्षों को शुल्क एकत्र करने की अनुमति नहीं है**
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय संस्थान इन शुल्कों का भुगतान सीधे तीसरे पक्ष को करने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि उधारकर्ता सीधे वित्तीय संस्थानों को अपना बकाया भुगतान करते हैं।
Source: https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Notification.aspx?Id=12382&fn=2&Mode=0
https://www.livemint.com/companies/news/rbi-gives-green-signal-to-first-loss-default-guarantee-fldg-framework-heres-how-will-fintech-banks-nbfcs-benefit-11686244184070.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.25) निम्नलिखित समुद्रों पर विचार करें:
1. कारा
2. लापटेव
3. रॉस
4. चुक्ची
5. वेडेल
6. तिमोर
उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) में मार्ग के हिस्से के रूप में उपरोक्त कितने समुद्र शामिल हैं?
a) केवल तीन
b) केवल चार
c) केवल पांच
d) सभी छह

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

उत्तरी समुद्री मार्ग आर्कटिक महासागर के 4 समुद्रों तक फैला है, जो बैरेंट्स और कारा सागर के बीच की सीमा से शुरू होता है और बेरिंग जलडमरूमध्य में समाप्त होता है।

विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं: मार्ग में आर्कटिक महासागर के समुद्र शामिल हैं- कारा, लापतेव, पूर्वी साइबेरियाई और चुक्ची।

विकल्प 3, 5 और 6 गलत हैं: रॉस, वेडेल और तिमोर सागर अंटार्कटिका के समुद्र हैं जो उत्तरी समुद्री मार्ग का हिस्सा नहीं हैं।

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 16

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Northern Sea Route

Q.26) निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:

1. ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
2. सरकार द्वारा RBI से ऋण लेना
3. RBI द्वारा बैंकों के लिए आरक्षित अनुपात सीमा बढ़ाना
4. रेपो रेट को कम करना

उपर्युक्त में से कितनी कार्रवाइयों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) केवल तीन

d) सभी चार

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

मुद्रा आपूर्ति में किसी देश की अर्थव्यवस्था के भीतर सभी परिसंचारी मुद्रा और आसानी से परिवर्तनीय बैंक जमा शामिल होती हैं, जो एक निश्चित समय पर उपलब्ध कुल तरल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें प्रचलन में भौतिक नकदी के साथ-साथ बैंक जमा भी शामिल है जिसे खाताधारक आसानी से नकदी के रूप में उपयोग और उपयोग कर सकते हैं।

विकल्प 1 गलत है: ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री: OMO में खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना शामिल है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि जब RBI सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, तो यह बाजार से धन अवशोषित करता है, जिससे बैंकों के लिए उपलब्ध तरलता और समग्र धन आपूर्ति कम हो जाती है।

विकल्प 2 सही है: सरकार द्वारा RBI से ऋण लेना: जब सरकार RBI से उधार लेती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि RBI सरकार के खाते में पैसा जमा करता है और प्रभावी ढंग से अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है।

विकल्प 3 गलत है: RBI द्वारा आरक्षित अनुपात सीमा बढ़ाना: RBI द्वारा आरक्षित अनुपात सीमा बढ़ाने से धन आपूर्ति कम हो जाती है। आरक्षित अनुपात जमा देनदारियों का वह हिस्सा है जिसे बैंकों को उधार देने के बजाय आरक्षित रखना आवश्यक है। जब आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है, तो बैंकों को अपनी जमा राशि का अधिक हिस्सा आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उधार देने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार धन आपूर्ति कम हो जाती है।

विकल्प 4 सही है: RBI द्वारा नीतिगत रेपो दर को कम करना: रेपो दर को कम करने से धन आपूर्ति बढ़ जाती है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। जब रेपो दर कम हो जाती है, तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण देने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। यह ऋण लेने और व्यय करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे धन आपूर्ति का विस्तार होता है।

Source: Vivek Singh Economy book. Chapter 2 money and banking part 1. Subject:) Economy

Subtopic:) Monetary Policy

WWW.PDFNOTES.CO

Q.27) 'पेमेंट बैंक' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे व्यक्तिगत ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपये की जमा राशि ले सकते हैं।
2. उन्हें आरबीआई द्वारा अनिवार्य वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने की आवश्यकता है।
3. वे ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
4. वे जनता से सावधि जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भुगतान बैंक वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें सीमित श्रेणी की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जो मुख्य रूप से भुगतान और प्रेषण पर केंद्रित हैं। उन्हें ग्राहकों से जमा स्वीकार करने, डेबिट कार्ड जारी करने, धन हस्तांतरण की सुविधा देने और अन्य बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। हालाँकि, उन्हें ऋण या क्रेडिट कार्ड देने की अनुमति नहीं है। भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य आबादी के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले वर्गों तक पहुंच कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इसकी अनुशंसा नचिकेत मोर समिति ने की थी.
कथन 1 गलत है: भुगतान बैंकों के लिए जमा सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। नवंबर 2014 में भुगतान बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों ने शुरू में उन्हें प्रति व्यक्तिगत ग्राहक को अधिकतम 1 लाख रुपये का बैलेंस रखने की अनुमति दी थी। हालाँकि, उनके प्रदर्शन की समीक्षा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को समर्थन देने के लक्ष्य के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सीमा को प्रति व्यक्तिगत ग्राहक ₹2 लाख तक बढ़ा दिया गया है।
कथन 2 सही है: भुगतान बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) को पूरा करने के हिस्से के रूप में एक वर्ष तक की परिपक्वता के साथ अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों या ट्रेजरी बिलों में अपने "मांग जमा शेष" का न्यूनतम 75% निवेश करना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: भुगतान बैंकों को अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। हालाँकि, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
कथन 4 सही है: भुगतान बैंकों को सावधि जमा या NRI जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।
Source: https://www.livemint.com/industry/banking/payments-bank-deposit-limit-doubled-by-rbi-11617772815778.html
https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/rbi-doubles-deposit-limit-of-payments-banks-to-2-lakh/article34264054.ece
https://www.livemint.com/money/personal-finance/payments-banks-knock-on-rbi-s-door-for-small-value-deposits-report-airtel-fino-india-post-jio-nsdl-paytm-fds-11708682031639.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.28) 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (**Priority Sector Lending**; PSL)' के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:
1. शहरी सहकारी बैंक (UCBs)।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)
4. विदेशी बैंक

WWW.PDFNOTES.CO

उपरोक्त में से कितने वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (**Priority Sector Lending**, PSL) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों पर लगाई गई एक नियामक आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके ऋण का एक हिस्सा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्देशित हो। इन क्षेत्रों में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और RBI द्वारा पहचाने गए अन्य क्षेत्र शामिल हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटित करना अनिवार्य है।
विकल्प 1 सही है: शहरी सहकारी बैंकों को अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके ऋण का एक निश्चित प्रतिशत कृषि, छोटे व्यवसाय और आवास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जाए।
विकल्प 2 सही है: आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य निर्धारित किया है।
विकल्प 3 गलत है: बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को प्रदान किए गए ऋण जो विशेष रूप से कृषि, छोटे व्यवसायों और कम आय वाले आवास जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) श्रेणी के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यह तंत्र प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों पर केंद्रित NBFC के माध्यम से वंचित क्षेत्रों तक ऋण पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन NBFC को स्वयं RBI द्वारा पीएसएल प्रदान करने का अधिदेश नहीं दिया गया है।
विकल्प 4 सही है: लघु वित्त बैंकों और विदेशी बैंकों को आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्य दिए जाते हैं।
Source: https://www.rbi.org.in/commonperson/English/scripts/FAQs.aspx?Id=1105
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1931050#:~:text=The%20Reserve%20Bank%20of%20India,extended%20to%20March%2031%2C2024.
https://vikaspedia.in/agriculture/agri-credit/credit-institutions/priority-sector-lending
https://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=87#:~:text=a)%20Classification%20under%20PSL%3A&text=The%20banks%20can%20classify%20on,the%20funds%20from%20the%20ban
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.29) बैंकों द्वारा ऋण माफ़ (Loan Write-off) करने की प्रथा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: बैंकों द्वारा ऋण को राइट-ऑफ करने की प्रथा उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को हटाकर अपनी बैलेंस शीट को साफ करने में सक्षम बनाती है।
कथन-II: जिन ऋणों को राइट-ऑफ कर दिया जाता है उन्हें 'हानि संपत्ति (Loss assets)' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि बैंक उधारकर्ताओं से इन ऋणों को वापस लेने का अधिकार खो देते हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या है।
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या नहीं है।
c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
d) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

कथन I सही है: बैंक मुख्य रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को संबोधित करने और कर देनदारियों का प्रबंधन करने के लिए ऋण माफ़ी का सहारा लेते हैं। जब किसी ऋण को राइट-ऑफ कर दिया जाता है, तो उसे परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाना बंद हो जाता है, जिससे बैंक की बैलेंस शीट पर एनपीए का स्तर कम हो जाता है। आगे ऋण राइट-ऑफ से बैंकों की कर देनदारियों को कम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि वे बैंकों के मुनाफे से राइट-ऑफ ऋण राशि की कटौती की अनुमति देते हैं।

कथन-II गलत है: जब किसी ऋण को राइट-ऑफ कर दिया जाता है, तो इसका मतलब बैंक के रिकॉर्ड से ऋण को हटाना है, लेकिन इसका मतलब ऋण को रद्द करना नहीं है, न ही बैंक राइट-ऑफ किए गए ऋण पर अपना दावा छोड़ देते हैं। ऋण खाता सक्रिय रहता है, और ऋणदाताओं को भविष्य में राशि की वसूली की उम्मीद बनी रहती है।

घाटे वाली संपत्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा परिभाषित एक और अवधारणा है, जिसे बैंक द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पहचानी गई संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से राइट-ऑफ नहीं किया जाता है। लॉस असेट्स वे NPA हैं जिनका भुगतान न करने की विस्तारित अवधि होती है, इसलिए इन्हें बैंकों की परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करना अब उचित नहीं है।

Source:
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=12185#:~:text=loss%20has%20been-,identified,-by%20the%20bank
https://forumias.com/blog/what-is-a-loan-write-off-and-why-do-banks-do-it/#What_is_a_loan_write-off:~:text=it%20will%20no-,longer,-be%20counted%20as

Subject:) Economy

Subtopic:) Banking

Q.30) संसदीय चयन समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये तदर्थ समितियाँ हैं जिसका अर्थ है कि उद्देश्य पूरा होने पर इसे भंग कर दिया जाएगा।
2. राज्यसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, केवल एक मंत्री ही यह कहते हुए संशोधन पेश कर सकता है कि किसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए।
3. समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

कथन 1 सही है: संसदीय चयन समितियाँ प्रकृति में तदर्थ अर्थात् अस्थायी होती हैं। इनका गठन विशिष्ट बिलों या मुद्दों की जांच के लिए किया जाता है। एक बार जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वे विघटित हो जाते हैं।

कथन 2 गलत है: राज्य सभा के नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 125 के तहत, कोई भी सदस्य (सरकारी और निजी दोनों सदस्य) किसी विधेयक को चयन समिति को भेजने के लिए संशोधन पेश कर सकते हैं। इसलिए यह सरकारी सदस्यों तक ही सीमित नहीं है।

कथन 3 गलत है: चयन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति/लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 7

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Parliamentary Select Committee

WWW.PDFNOTES.CO

Q.31) भारत में, 'अंतिम उपाय के ऋणदाता' के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है?
1. व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण देना जब वे अन्य स्रोतों से उधार लेने में विफल हो जाते हैं।
2. अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता उपलब्ध कराना।
3. बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को ऋण देना।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 2 और 3
d) केवल 3

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
अंतिम उपाय का ऋणदाता एक संस्था है, आमतौर पर देश का केंद्रीय बैंक, जो उन बैंकों या अन्य योग्य संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं या जिन्हें अत्यधिक जोखिम भरा या पतन के करीब माना जाता है।
अंतिम उपाय के ऋणदाता उन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं जिन्होंने धन जमा किया है और ग्राहकों को अस्थायी सीमित तरलता वाले बैंकों से घबराहट से पैसे निकालने से रोकते हैं। वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर अंतिम उपाय के ऋणदाता से उधार नहीं लेने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऐसी कार्रवाई से संकेत मिलता है कि बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।
Source: UPSC CSE PRE. 2021
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.32) क्रेडिट नियंत्रण विधियों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें:
1. क्रेडिट राशनिंग
2. नैतिक प्रेरणा (Moral Suasion)
3. रेपो रेट
4. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility)
उपरोक्त में से कितने विकल्प चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण के तरीके हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
ऋण नियंत्रण के गुणात्मक तरीकों को ऋण नियंत्रण के चयनात्मक उपकरण भी कहा जाता है। चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण को क्रेडिट नियंत्रण के सामान्य उपकरणों से बेहतर माना जाता है क्योंकि वे न केवल क्रेडिट की कुल मात्रा को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित होते हैं बल्कि उन विशिष्ट उपयोगों को भी नियंत्रित करते हैं जिनके लिए क्रेडिट दिया जाता है।
कथन 1 सही है: क्रेडिट राशनिंग चयनात्मक नियंत्रण का एक साधन है। क्रेडिट राशनिंग के तहत, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समग्र आधार पर या किसी विशेष उपयोग के लिए दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा तय करता है। ब्याज की दर विभिन्न क्षेत्रों या उपयोगों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
कथन 2 सही है: नैतिक दबाव चयनात्मक नियंत्रण का एक साधन है। नैतिक दबाव के तहत, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऐसी क्रेडिट नीति अपनाने के लिए प्रेरित और दबाव डालता है जो अर्थव्यवस्था के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हो।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 3 गलत है: रेपो दर मात्रात्मक मौद्रिक नीति का एक साधन है, जहां केंद्रीय बैंक उस दर को निर्धारित करके अर्थव्यवस्था में ऋण के समग्र स्तर को प्रभावित करता है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से आरक्षित उधार ले सकते हैं।
कथन 4 गलत है: स्थायी जमा सुविधा (SDF) भी मात्रात्मक मौद्रिक नीति का साधन है, जो अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को प्रभावित करती है, जहां बैंक केंद्रीय बैंक के पास अधिशेष निधि जमा करते हैं और उन पर ब्याज कमाते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने में मदद करता है।
ज्ञानधार:
ऋण नियंत्रण के सभी उपकरणों को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
(a) क्रेडिट नियंत्रण के मात्रात्मक तरीके
(b) क्रेडिट नियंत्रण के गुणात्मक या चयनात्मक तरीके
इन्हें मौद्रिक नीति के उपकरण कहा जाता है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीति है।
गुणात्मक नियंत्रण नीति उपकरणों के उदाहरण:
1) क्रेडिट राशनिंग।
2) मार्जिन आवश्यकताएँ।
3) नैतिक प्रेरणा।
4) उपभोक्ता ऋण विनियमन।
5) दिशानिर्देश।
मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरणों के उदाहरण:
1) नकद आरक्षित अनुपात (CRR)।
2) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।
3) ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs)
4) रेपो रेट।
Source: 318_Economics_Eng_Lesson28.pdf (nios.ac.in)
https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/13616/1/Unit-7.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.33) 'फैक्टरिंग' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
a) यह अल्पकालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यवसाय द्वारा किसी विशेष वित्तीय कंपनी या तीसरे पक्ष को इनवॉइस बेचने की प्रथा को दर्शाता है।
b) यह कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ के बजाय इक्विटी शेयर प्रदान करने की प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है।
c) यह बंद होने के जोखिम को कम करने के लिए एक बड़ी कंपनी को छोटे, स्वतंत्र व्यवसायों में विभाजित करने की प्रथा है।
d) यह उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान न करने के जोखिम को कम करने के लिए उधारकर्ताओं को चरणों में ऋण वित्तीय संस्थान प्रदान करने की प्रथा को दर्शाता है।

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
विकल्प a सही है: फैक्टरिंग एक वित्तीय लेनदेन है जहां एक व्यवसाय अपनी अल्पकालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बिना भुगतान किए गए इनवॉइसो/बिलों को एक विशेष वित्तीय कंपनी (फैक्टर) को छूट पर बेचता है। कारक नकदी के बदले में व्यवसाय से इनवॉइस खरीदता है, जिसे व्यवसाय मूल इनवॉइस के परिपक्व होने तक इंतजार करने के बजाय तुरंत उपयोग कर सकता है। जब इनवॉइस परिपक्व हो जाता है, तो देनदार मूल राशि कारक को चुकाएगा, न कि व्यवसाय को।
डिफ़ॉल्ट के जोखिम के आधार पर, फैक्टरिंग को रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन-रीकोर्स फैक्टरिंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। रिकोर्स फैक्टरिंग में, कारक डिफ़ॉल्ट का जोखिम नहीं मानता है। यदि देनदार चुकाने में विफल रहता है, तो कंपनी

WWW.PDFNOTES.CO

ऋण के लिए उत्तरदायी रहती है। इसके विपरीत, नॉन-रीकोर्स फैक्टरिंग में, फैक्टर खराब ऋण का जोखिम उठाता है, और यदि देनदार चूक करता है तो वह कंपनी से धन की वसूली नहीं कर सकता है।

Source: https://economictimes.indiatimes.com/definition/factoring
https://razorpay.com/learn/business-banking/factoring/#What-is-Factoring:~:text=of%20factoring%2C%20the-,factor,-does%20not%20take
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.34) फंड ट्रांसफर के NEFT और RTGS मोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. RTGS लेनदेन वास्तविक समय में होता है जबकि NEFT लेनदेन स्थगित निपटान मोड में होता है।
2. RTGS के विपरीत, NEFT में कोई न्यूनतम स्थानांतरण मूल्य नहीं है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
कथन 1 सही है. NEFT एक स्थगित निपटान मोड में काम करता है, जहां लेनदेन को बैचों में संसाधित और निपटान किया जाता है। निपटान प्रति घंटे के अंतराल में होता है। इसके विपरीत, RTGS वास्तविक समय में लेनदेन का निपटान करता है, जिसका अर्थ है कि धनराशि तुरंत लाभार्थी के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
कथन 2 सही है. NEFT में, किसी भी राशि का फंड ट्रांसफर शुरू किया जा सकता है। लेन-देन राशि की कोई ऊपरी या निचली सीमा नहीं है। RTGS में, प्रति लेनदेन कम से कम ₹2 लाख का फंड ट्रांसफर आवश्यक है, आपके द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली राशि पर कोई विशेष ऊपरी सीमा नहीं है।

Source: https://www.hdfcbank.com/personal/resources/learning-centre/pay/difference-between-neft-and-rtgs
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.35) हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने के लिए की गई पहल के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों और उनसे जुड़े स्थानों पर विचार करें:

राष्ट्रीय जलमार्ग	**लिंक करता है**
1. राष्ट्रीय जलमार्ग 1	हल्दिया-इलाहाबाद
2. राष्ट्रीय जलमार्ग 2	धुबरी-सदिया
3. राष्ट्रीय जलमार्ग 3	काकीनाडा-पुडुचेरी
4. राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कोट्टापुरम-कोल्लम

ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

युग्म 1 सही है: राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। NW 1 पश्चिम बंगाल में हल्दिया को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से जोड़ता है। यह कुल 1620 किमी की दूरी तक फैला हुआ है।

युग्म 2 सही है: राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। NW 2 असम में स्थित धुबरी और सदिया शहर को जोड़ता है।

युग्म 3 गलत है: राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जिसे पश्चिमी तट नहर के रूप में भी जाना जाता है, भारत के केरल में स्थित अंतर्देशीय नौवहन मार्ग का 205 किमी लंबा हिस्सा है। यह केरल में स्थित कोल्लम और कोट्टापुरम को जोड़ता है।

युग्म 4 गलत है: राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा-गोदावरी नदी पर घोषित है। यह पुडुचेरी को आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से जोड़ता है। यह भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को जोड़ता है।

Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 27

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) National waterways

Q.36) यदि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुग्राही रुख (Accommodative Stance) अपनाया है, तो इसका क्या मतलब है?

a) RBI आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है।

b) RBI मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है।

c) RBI या तो नीतिगत दर में कटौती करता है या नीतिगत दर बढ़ाता है।

d) RBI कुछ समय के लिए ब्याज दरों को कम करने से बच सकता है और उन्हें धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू कर सकता है।

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

विकल्प a सही है. उदार रुख का मतलब है कि RBI आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है। RBI, एक उदार नीति अवधि के दौरान, ब्याज दरों में कटौती करने को तैयार है। दरों में बढ़ोतरी से इनकार किया गया है. केंद्रीय बैंक आमतौर पर एक उदार नीति अपनाता है जब विकास को नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होती है और मुद्रास्फीति तत्काल चिंता का विषय नहीं होती है।

विकल्प b ग़लत है. आक्रामक रुख (Hwakish Stance) से संकेत मिलता है कि RBI की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है। ऐसे चरण के दौरान, RBI धन आपूर्ति पर अंकुश लगाने और इस प्रकार मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने को तैयार है। एक आक्रामक नीति सख्त मौद्रिक नीति का भी संकेत देती है। ऐसी अवधि के दौरान दर में कटौती लगभग तय है। जब केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाता है या मौद्रिक नीति को 'संकुचित' करता है, तो बैंक भी अंतिम उधारकर्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज दर बढ़ाते हैं, जो बदले में वित्तीय प्रणाली में मांग पर अंकुश लगाता है।

विकल्प c ग़लत है. 'तटस्थ रुख (Neutral Stance)' से पता चलता है कि RBI या तो दरों में कटौती कर सकता है या दरें बढ़ा सकता है। यह रुख आम तौर पर तब अपनाया जाता है जब नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति और विकास दोनों पर समान होती है। तटस्थ नीति के दौरान, केंद्रीय बैंक दरों में बढ़ोतरी या कटौती के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। आने वाले डेटा के आधार पर ब्याज दर किसी भी तरफ जा सकती है।

विकल्प d गलत है. RBI अक्सर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि वे कुछ समय के लिए ब्याज दरों को कम करने से बचते हैं और धीरे-धीरे उन्हें बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे हर बैठक में दरें बढ़ाएं, लेकिन कुल मिलाकर, वे उन्हें बढ़ाने की ओर झुक रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे निर्धारित बैठकों के बाहर भी दरें बढ़ा सकते हैं।

Source: https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/rbi-mpc-meeting-interest-rate-inflation-accomodation-explained-8885421/

https://www.moneycontrol.com/news/business/explained-accommodative-neutral-and-hawkish-stances-in-rbi-monetary-policy-8066221.html

WWW.PDFNOTES.CO

https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/rbi-mpc-meeting-interest-rate-inflation-accomodation-explained-8885421/
Subject:) Economy
Subtopic:) Monetary Policy

Q.37) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

भुगतान साधन	**उनके कार्य**
1. भारत बिल भुगतान प्रणाली	उपयोगिता सेवाओं के मासिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है
2. नेशनल फाइनेंशियल स्विच	भारत के साझा एटीएम के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में काम करता है
3. E-RUPI	व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर
4. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	इंटरबैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
भारत में भुगतान उपकरणों में डिजिटल भुगतान विधियां, प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) और अन्य भुगतान उपकरण शामिल हैं।
युग्म 1 सही सुमेलित है: भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) एक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अवधारणा है जो ग्राहकों को कार्ड, NEFT इंटरनेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, आधार आधारित भुगतान और कई तरीकों का उपयोग करके बिलों का भुगतान करने की अनुमति देती है। BBPS SMS या रसीद के माध्यम से भुगतान की तत्काल पुष्टि भी प्रदान करता है। BBPS कई बिल संग्रह श्रेणियां प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस और पानी के बिल।
युग्म 2 सही सुमेलित है: नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS) भारत का साझा एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो नकद निकासी, कार्ड-टू-कार्ड फंड ट्रांसफर और नकद जमा की अनुमति देता है। यह नकदी जमा मशीनों और रिसाइक्लर्स सहित 2.57 लाख से अधिक एटीएम से जुड़ा है। NFS ग्राहकों को बैंकों के स्विचों के बीच इंटर कनेक्टिविटी के माध्यम से एटीएम लेनदेन को रूट करके कनेक्टेड बैंक के किसी भी एटीएम का उपयोग करने की अनुमति देता है।
NFS को 2004 में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा डिजाइन, विकसित और तैनात किया गया था। इसे 2009 में IDRBT से NPCI ने ले लिया था।
युग्म 3 सही सुमेलित है: E-RUPI एक व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर है। यह भारतीय रुपये के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, जिसे विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस निर्बाध एकमुश्त भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता E-RUPI स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर बिना कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। E-RUPI को किसी विशिष्ट उद्देश्य या गतिविधि के लिए संगठनों या सरकार द्वारा एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से लाभार्थियों के साथ साझा किया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने वित्तीय सेवा विभाग (DFS), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और साझेदार बैंकों के साथ मिलकर एक अभिनव डिजिटल समाधान - 'E-RUPI' लॉन्च किया है।
युग्म 4 सही सुमेलित है: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट्स और सरकार के लिए "नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH)" लागू किया है, जो इंटरबैंक, उच्च मात्रा, दोहराए जाने वाले

WWW.PDFNOTES.CO

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा के लिए एक वेब आधारित समाधान है तथा प्रकृति में आवधिक है। NACH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर लेनदेन करने के लिए और टेलीफोन, बिजली, पानी, ऋण, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि से संबंधित भुगतानों के संग्रह के लिए बड़े पैमाने पर लेनदेन के लिए किया जा सकता है। .

Source: https://www.npci.org.in/what-we-do/nach/product-overview
https://www.npci.org.in/what-we-do/e-rupi/product-overview
https://www.bharatbillpay.com/about/
https://www.npci.org.in/what-we-do/nfs/product-overview#:~:text=National%20Financial%20Switch%20taken%20over%20by%20NPCI,2.57%20Lac%20ATMs%20(including%20cash%20deposit%20machines/recyclers).
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.38) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit societies; PACS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में कार्य करते हैं।
2. वे सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) जमीनी स्तर की संस्थाएँ हैं, और उनकी सदस्यता में व्यक्तिगत किसान, कारीगर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्य शेयरधारक के रूप में शामिल हैं।
कथन 1 ग़लत है: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं। वे राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
कथन 2 सही है: वे देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) संरचना के सबसे निचले स्तर का गठन करते हैं, जो अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण और अन्य इनपुट सेवाएं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण, आदि प्रदान करते हैं। सदस्य किसान. इन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (STCC) के माध्यम से पुनर्वित्त किया जाता है।
Source: https://www.nabard.org/digitalizing-cooperatives.aspx
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2755#:~:text=PACS%20are%20outside%20the%20purview,regulated%20by%20the%20Reserve%20Bank.
https://www.cooperation.gov.in/about-primary-agriculture-cooperative-credit-societies-pacs
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.39) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किए गए हैं।
2. DRTs के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

WWW.PDFNOTES.CO

3. उनके पास सिविल अदालतों की शक्ति है, जैसे ट्रिब्यूनल में किसी भी गवाह को समन देना और उपस्थिति को दर्ज करना।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) प्रणाली का कार्यान्वयन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की बढ़ती समस्या और ऋण वसूली से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता का सीधा जवाब था।
कथन 1 गलत है: ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRATs) की स्थापना ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम (RDB अधिनियम), 1993 के तहत शीघ्र न्यायनिर्णयन प्रदान करने और ऋणों की वसूली के विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी। बैंक और वित्तीय संस्थान।
कथन 2 सही है: केंद्र सरकार ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के पीठासीन अधिकारी (**Presiding Officer**; PO) की नियुक्ति करती है। PO DRT का प्रमुख होता है और पुनर्नियुक्ति की संभावना के साथ पांच साल तक कार्य करता है। नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश होना चाहिए या बनने के लिए योग्य होना चाहिए।
कथन 3 सही है: ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है और DRT और DRAT के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।
वसूली अधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक सिविल अदालत में निहित हैं। निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:
1) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जांच करना;
2) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;
3) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;
5) अपने निर्णयों की समीक्षा करना;
Source: https://financialservices.gov.in/beta/en/page/information-related-debt-recovery-tribunal-section
https://financialservices.gov.in/beta/en/page/debts-recovery-tribunals-debts-recovery-appellate-tribunals
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.40) 'हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) बहते पानी के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न बिजली।
b) पृथ्वी के कोर की गर्मी से उत्पन्न बिजली।
c) नम हवा में मौजूद नमी से उत्पन्न बिजली।
d) ज्वार के बढ़ने और गिरने के दौरान समुद्र के पानी में उछाल से उत्पन्न बिजली।

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी का तात्पर्य आर्द्र हवा में मौजूद नमी से उत्पन्न बिजली से है।
दो इलेक्ट्रोड और एक युक्त छोटे उपकरण का उपयोग करके नम हवा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है

WWW.PDFNOTES.CO

नैनोपोर्स से भरी सामग्री की पतली परत। 100 नैनोमीटर (NM) से कम व्यास वाले ये नैनोपोर्स, हवा से पानी के अणुओं को डिवाइस से गुजरने की अनुमति देते हैं।
जैसे ही ये अणु ऊपरी कक्ष से निचले कक्ष की ओर बढ़ते हैं, वे नैनो छिद्रों के किनारों के साथ संपर्क करते हैं, जिससे कक्षों के बीच विद्युत आवेश असंतुलन पैदा होता है। यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से डिवाइस को एक लघु बैटरी में बदल देती है, जिससे निरंतर बिजली पैदा होती है।
Source: Forum IAS quarterly current affairs magazine for prelims, July-September2023, Page- 47
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) Hygroelectricity

Q.41) वित्त के संदर्भ में, शब्द 'बीटा' किसे निर्दिष्ट करता है?
a) अलग-अलग प्लेटफॉर्मों से, साथ-साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया
b) किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की, जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की, निवेश कार्यनीति
c) एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम, जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है
d) एक संख्यात्मक मान, जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
बीटा: समग्र बाज़ार गतिविधियों के संबंध में किसी स्टॉक की अपेक्षित गतिविधि को बीटा नामक अवधारणा द्वारा मापा जाता है। 1 से अधिक बीटा वाले स्टॉक को व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर माना जाता है, जबकि 1 से कम बीटा वाले स्टॉक को कम अस्थिर माना जाता है।
कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल (सीएपीएम), एक मॉडल जो स्टॉक के रिटर्न की गणना करता है, बीटा को अपने प्राथमिक कारक के रूप में उपयोग करता है। बीटा गणना का उपयोग स्टॉक की अस्थिरता और उससे जुड़े व्यवस्थित जोखिम का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।
Source: UPSC CSE PRE. 2023
Subject:) Economy
Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.42) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
3. यह भारत में दिवाला पेशेवरों (आईपी) के नामांकन के लिए परीक्षण आयोजित करता है।
4. यह कंपनियों के दिवालियेपन के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक निर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है।
कथन 1 सही है : भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को 2016 में अधिनियमित दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत **एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।**

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 2 सही है: आईबीबीआई **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।**

कथन 3 सही है: आईबीबीआई भारत में **दिवाला पेशेवरों (आईपी) और दिवाला पेशेवर एजेंसियों (** आईपीए) के लिए परीक्षण आयोजित करता है और प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित मामलों पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है। यह दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संस्थाओं के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार और लागू करता है।

कथन 4 गलत है: आईबीबीआई **दिवाला आवेदनों पर निर्णय लेने में शामिल नहीं है।** इसके बजाय, यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज की देखरेख करता है। दिवालियेपन के मामलों का वास्तविक **निर्णय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) जैसे निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।**

ज्ञानधार:

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की संरचना:

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है,

1) **अध्यक्ष** .

2) **केंद्र सरकार के अधिकारियों में से तीन सदस्य** संयुक्त सचिव के समकक्ष या उससे नीचे के स्तर के नहीं। तीन सदस्यों में से **प्रत्येक वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और कानून मंत्रालय का पदेन प्रतिनिधित्व करेगा** ।

1) **आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा नामित** एक सदस्य , पदेन।

2) **केंद्र सरकार द्वारा नामांकित पांच अन्य सदस्य** , जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) का कार्यकाल पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष पूरे होने तक, जो भी पहले हो, है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

Source: https://ibbi.gov.in/en/about

https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/about-us/affiliated-offices/ibbi.html

https://cleartax.in/s/insolvency-bankruptcy-board-india

Subject:) Economy

Subtopic:) Banking

Q.43) हाल ही में शुरू किए गए 'T+0 व्यापार निपटान चक्र' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड:

1. इस प्रणाली के तहत, प्रतिभूतियों और निधियों का निपटान व्यापार के अगले दिन तक किया जाएगा।
2. इस निपटान प्रणाली से निवेशकों और ब्रोकरेज फर्मों दोनों के लिए व्यापार की समग्र लेनदेन लागत कम हो सकती है।
3. यह भारतीय बाजारों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 28 मार्च, 2024 से T+0 व्यापार निपटान चक्र शुरू करने के लिए तैयार है। नियामक ने इसे वैकल्पिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया है।

कथन 1 गलत है: टी+0 निपटान चक्र में, **ट्रेडों का निपटान उसी दिन किया जाता है** जिस दिन लेनदेन होता है, पारंपरिक टी+1 चक्र से हटकर। इसका मतलब है कि शेयर खरीदार के खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और धन व्यापार के उसी दिन विक्रेता के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 2 सही है : T+0 निपटान में **लेनदेन लागत कम करने की क्षमता है** । वास्तविक समय निपटान को सक्षम करके, **T+0 चक्र प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और** विलंबित निपटान से जुड़ी लागत को कम करता है। कम निपटान जोखिम से संभावित चूक से जुड़ी फीस कम हो सकती है।

कथन 3 सही है: T+0 निपटान जोखिम प्रबंधन और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए कई लाभ प्रदान करता है:

1) **निपटान जोखिम में कमी** : निपटान विंडो को छोटा करने से व्यापार तिथि और निपटान तिथि के बीच किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्व (डिफ़ॉल्ट) को पूरा करने में विफल होने की संभावना कम हो जाती है।

2) **बढ़ी हुई बाजार दक्षता** : तेजी से निपटान व्यापार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके समग्र बाजार दक्षता में सुधार कर सकता है।

3) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: T+0 प्रणाली संभावित रूप से अन्य विकसित बाजारों के साथ निपटान प्रथाओं को संरेखित करके विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजारों को अधिक आकर्षक बना सकती है।

Source: https://business.outlookindia.com/markets/what-is-t0-settlement-cycle-and-how-will-it-impact-the-stock-market-and-investors

https://www.icicidirect.com/research/equity/finace/what-is-t-0-settlement-cycle-introduced-by-sebi#:~:text=This%20innovative%20system%20enables%20the,providing%20immediate%20liquidity%20to%20investors.

https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/t0-instant-settlement-cycle-sebi-markets-explained-9083167/

Subject:) Economy

Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.44) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में वित्तीय संस्थानों को शामिल करने के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इन वित्तीय संस्थानों के शाखा विस्तार प्रयासों को सीमित करता है।
2. यह इन वित्तीय संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से रोकता है।
3. यह इन वित्तीय संस्थानों को शासन संबंधी मामलों में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
4. इसके लिए प्रमोटरों और शेयरधारकों को इन वित्तीय संस्थानों में अधिक पूंजी डालने की आवश्यकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निगरानी में रखा जाता है ।

पीसीए ढांचे के तहत वित्तीय संस्थानों को **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है (विवरण 2 गलत है)।**

बल्कि इन संस्थानों को **सुधारात्मक उपायों का सामना करना पड़ता है** जैसे:

1) शाखा विस्तार गतिविधियों और लाभांश वितरण या लाभ प्रेषण पर प्रतिबंध **(विवरण 1 सही है)**

2) **पीसीए प्रमोटरों या शेयरधारकों को** संबंधित संस्थानों में अधिक पूंजी लगाने और ऐसे संस्थानों के उत्तोलन को कम करने का आदेश देता है। **(कथन 4 सही है)**

3) शासन, पूंजी, लाभप्रदता और व्यावसायिक संचालन के संबंध में विवेकाधीन निर्णयों पर प्रतिबंध। नतीजतन, पीसीए ढांचे के तहत संस्थानों को अपने शासन मामलों के प्रबंधन में बढ़ी हुई स्वायत्तता नहीं दी जाती है **(कथन 3 गलत है)।**

WWW.PDFNOTES.CO

4) समूह कंपनियों के लिए **गारंटी जारी करने या आकस्मिक देनदारियां लेने पर प्रतिबंध ।**
ज्ञान का आधार: पीसीए का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा कड़ी जांच के तहत रखकर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या की जांच करना है। वित्तीय संस्थानों के जोखिम कारक की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक हैं **(i) संपत्ति पर रिटर्न (ii) पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) और (iii) गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) अनुपात।**
Source: https://forumias.com/blog/state-owned-nbfcs-put-under-pca-norms/#:~:text=Restriction%20on%20dividend-,distribution,-/remittance%20of%20profit
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12208&Mode=0
https://www.livemint.com/industry/banking/rbi-extends-pca-framework-to-government-owned-nbfcs-from-october-2024-11696938419054.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Banking

Q.45) हाल ही में समाचारों में देखे गए 'शॉर्ट सेलिंग' शब्द के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी प्रकार की शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी है।
कथन-II: शॉर्ट सेलिंग में उस स्टॉक को बेचना शामिल है जो विक्रेता के पास व्यापार के समय नहीं होता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही व्याख्या है।
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है।
c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
d) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
कथन-I गलत है : **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन नग्न शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है।** इसलिए यह कथन कि सेबी द्वारा सभी प्रकार की शॉर्ट सेलिंग प्रतिबंधित है, गलत है।
सेबी ने यह भी स्पष्ट किया कि वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में कारोबार करने वाले सभी स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के लिए पात्र हैं। सेबी ने निवेशकों को निपटान के समय प्रतिभूतियां वितरित करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य किया। **नेकेड शॉर्ट सेलिंग** एक ऐसी प्रथा है जहां **शेयर पहले से उधार लिए बिना बेचे जाते हैं।** इन्हें बाद में कम कीमत पर वापस खरीदने और ब्रोकर के पास लौटकर लाभ कमाने की उम्मीद से लाया जाता है। यह **पारंपरिक लघु बिक्री** से भिन्न है जिसमें बाजार में बेचने से पहले ब्रोकर से शेयर उधार लेना शामिल है।
कथन II सही है: शॉर्ट सेलिंग में उस स्टॉक को बेचना शामिल है जो विक्रेता के पास व्यापार के समय नहीं होता है। यह भविष्य में शेयरों की कीमत में गिरावट की प्रत्याशा में स्थापित एक व्यापारिक रणनीति है । व्यापारी आमतौर पर छोटी बिक्री करने के लिए ब्रोकरेज के माध्यम से शेयर उधार लेते हैं, उनका मानना है कि मूल्य में कमी आएगी। बाद में, वे कीमत के अंतर से लाभ कमाने के लक्ष्य से कम कीमत पर शेयर वापस खरीदते हैं। हालाँकि, यदि इसके बजाय शेयर की कीमत बढ़ती है, तो व्यापारियों को अधिक कीमत पर शेयर खरीदना होगा, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होगा।
Source:
https://www.investopedia.com/terms/n/nakedshorting.asp#:~:text=still%20doesn%27t%20occur.-,Naked,-shorting%20is%20when
https://indianexpress.com/article/explained/everyday-explainers/hindenburg-research-accused-the-adani-fraud-short-seller-8406285/
https://www.businesstoday.in/markets/top-story/story/sebi-bans-naked-short-selling-no-institutional-investor-shall-be-allowed-to-do-day-trading-412081-2024-01-05

WWW.PDFNOTES.CO

https://www.livemint.com/money/demat-account-what-is-short-selling-and-how-does-it-work-mintgenie-explains-short-selling-steps-in-trading-account-11711619039152.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Money Market/Capital Market

Q.46) 26 जनवरी 2009 को सोमवार था. 25 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था ?
a) रविवार
b) शनिवार
c) शुक्रवार
d) गुरुवार

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
2008 2 विषम दिनों वाला एक लीप वर्ष था और 2007 1 विषम दिन वाला एक गैर-लीप वर्ष था। इसलिए 26 जनवरी 2008 सोमवार से 2 दिन पहले था जो कि शनिवार है और इसी तरह 26 जनवरी 2007 शनिवार से 1 दिन पहले था जो कि शुक्रवार है।
अतः 25 जनवरी 2007 को गुरुवार था।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Logical and Verbal Reasoning

Q.47) कुछ तीन अंकों की संख्याएँ ऐसी होती हैं, जब हम संख्याओं के इकाई स्थान और 100वें स्थान को आपस में बदलते हैं तो हमें संख्याओं के बीच 297 का अंतर मिलता है। ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए?
a) 441
b) 491
c) 401
d) 411

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
माना कि तीन अंकों की संख्या 100x + 10y+z है
अंकों के आदान-प्रदान के बाद नई संख्या 100z + 10y+x होगी
प्रश्न के अनुसार अंकों का अंतर 297 है
100x+10y+z-(100z+10y+x) = 297
99x- 99z = 297
x - z = 297/99 = 3
=> XZ=3
विभिन्न संख्याओं के लिए x और z का मान
जब z = 1, x = 4
जब z = 2, x=5
जब z = 3, x=6
जब z = 4, x=7
जब z=5, x=8
ऐसी सबसे छोटी संख्या के लिए z, 1 होना चाहिए और x, 4 होना चाहिए
सबसे छोटी संख्या = 401 (y = 0 पर संख्या सबसे छोटी संख्या होगी)
विकल्प c सही होगा. Subject:) CSAT Subtopic:) Quantitative Aptitude

WWW.PDFNOTES.CO

Q.48) दो कक्षा A और B में क्रमशः 25 और 30 छात्र हैं। कक्षा-A में एक परीक्षा में उच्चतम अंक 50 और न्यूनतम अंक 30 है। उसी परीक्षा में कक्षा-B में उच्चतम अंक 70 और न्यूनतम अंक 20 है।
अब, पांच छात्रों को कक्षा-B से कक्षा-A में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उस परीक्षा के लिए कक्षा-B का औसत अंक निश्चित रूप से कम हो जाएगा।
2. उस परीक्षा के लिए कक्षा-A का औसत अंक निश्चित रूप से बढ़ेगा।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
कथन 1 गलत है : यदि कक्षा बी में सबसे कम यानी 20 अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्रों को कक्षा ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कक्षा बी का औसत वास्तव में बढ़ जाएगा क्योंकि कम प्रदर्शन करने वालों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
कथन 2 गलत है: यदि कक्षा बी में सबसे कम यानी 20 अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्रों को कक्षा ए में ले जाया जाता है, तो कक्षा ए का औसत वास्तव में घट जाएगा क्योंकि कक्षा ए का नया निम्न स्कोर 20 होगा जो पहले 30 था।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Quantitative Aptitude

निम्नलिखित 2 (दो) प्रश्नों के लिए दिशानिर्देश:
निम्नलिखित **दो** परिच्छेदों को पढ़ें और परिच्छेदों के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों पर आपके उत्तर केवल परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए।

परिच्छेद- I

हम कितना बचाते हैं और सरकारें उस बचत को कैसे निवेश करती हैं, इसके बीच का संबंध यह समझने में पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि देश कैसे बढ़ते और फलते-फूलते हैं। बचत को उस बीज के रूप में सोचें, जिसे जब सरकारों द्वारा सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण जैसी परियोजनाओं में समझदारी से बोया जाता है, तो सभी के लिए विकास और प्रगति हो सकती है। यह विचार नया नहीं है; यह लंबे समय से आर्थिक सोच का हिस्सा रहा है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि देशों के लिए दूसरों से बहुत अधिक उधार लेने के जाल में पड़े बिना महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निधि देने के लिए अपनी बचत बनाना कितना महत्वपूर्ण है।
हालाँकि, इस बचत को सफल निवेश में बदलना जो वास्तव में लोगों की मदद करता है और विकास को गति देता है, सीधा नहीं है। इसके लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि पैसा बुद्धिमानी से, खुले तौर पर और ऐसे तरीकों से खर्च किया जाए जो वास्तव में लंबे समय में देश की जरूरतों से मेल खाता हो। इसका मतलब है कि धन की बर्बादी या भ्रष्टाचार को फैलने से रोकने के लिए मजबूत प्रणालियां स्थापित करना, जो केवल उस अच्छे काम को ही छीन लेंगी जो यह पैसा कर सकता है। यह सिर्फ सरकारी खर्च से कहीं अधिक के बारे में भी है; यह व्यवसायों में भी रुचि और निवेश जगाने, एक ऐसी साझेदारी बनाने के बारे में है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों फंड व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं।
लेकिन बात यह है कि केवल बचत करने से स्वचालित रूप से बेहतर जीवन स्थितियां या विकास नहीं होता है। बहुत कुछ सुशासन और सही नीतियों पर निर्भर करता है। इनके बिना, बचत के संभावित लाभ ख़त्म हो सकते हैं, जिससे देश अभी भी बाहर से उधार लेने पर निर्भर रहेंगे। इसलिए, जब हम विकास की ओर ले जाने वाली बचत और निवेश के बारे में बात करते हैं, तो यह सिर्फ संख्याओं से कहीं अधिक है। यह इस बारे में है कि कोई देश अपने सभी लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए विचारशील निर्णयों और मजबूत, निष्पक्ष नीतियों द्वारा निर्देशित अपने संसाधनों का कितना अच्छा उपयोग कर सकता है।

WWW.PDFNOTES.CO

Q.49) परिच्छेद में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) बचत से लेकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया गया सरकारी निवेश ही किसी देश के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

b) बचत को सार्वजनिक निवेश में बदलने की प्रभावशीलता काफी हद तक पारदर्शी, बुद्धिमान खर्च और गलत आवंटन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत प्रणालियों के अस्तित्व पर निर्भर करती है।

c) निजी क्षेत्र का निवेश किसी देश के विकास के लिए सरकारी खर्च के पूरक में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है।

d) सार्वजनिक निवेश और विकास में बचत के प्रभावी उपयोग के लिए सुशासन और उचित नीति ढांचे अनावश्यक हैं।

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

विकल्प b (बचत को सार्वजनिक निवेश में बदलने की प्रभावशीलता काफी हद तक पारदर्शी, बुद्धिमान खर्च और गलत आवंटन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत प्रणालियों के अस्तित्व पर निर्भर करती है) परिच्छेद के दावे को दर्शाता है कि बचत को सफल सार्वजनिक निवेश में परिवर्तित करने के लिए न केवल बुद्धिमान और पारदर्शी व्यय की आवश्यकता होती है, बल्कि धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत संस्थागत ढाँचा । यह जनता की भलाई के लिए बचत को प्रभावी निवेश में बदलने की जटिलता पर परिच्छेद की चर्चा के अनुरूप है।

Subject:) CSAT

Subtopic:) Reading Comprehension

परिच्छेद- II

प्राकृतिक संसाधनों की खपत को लेकर चल रही बातचीत ने सतत विकास के मूल में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास को उजागर किया है। यह कथन पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की दीर्घकालिक अनिवार्यताओं के साथ प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त तत्काल आर्थिक लाभों को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके मूल में, यह बहस इस सवाल से जूझती है कि समाज भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे जारी रख सकता है। इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू "संसाधन अभिशाप" की अवधारणा है, यह घटना कुछ संसाधन संपन्न देशों में देखी गई है जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता समृद्धि के बजाय आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। यह प्रतिकूल परिणाम आर्थिक विकास, शासन और संसाधन प्रबंधन के बीच जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि प्रभावी नीतियों और शासन संरचनाओं के बिना, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए उपभोग पैटर्न के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, नवीकरणीय संसाधनों और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण की वकालत की जाती है। तकनीकी रूप से व्यवहार्य होते हुए भी यह बदलाव, मजबूत आर्थिक हितों और परिवर्तन के प्रति सामाजिक प्रतिरोध के रूप में पर्याप्त बाधाओं का सामना करता है। इसलिए, चुनौती न केवल इन संसाधनों की सीमित प्रकृति को पहचानने में है, बल्कि समग्र नीतियों को लागू करने में भी है जो स्थिरता, समानता और पर्यावरणीय अखंडता के बहुमुखी आयामों को संबोधित करती है।

Q.50) निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यदि सत्य है, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन की जटिलताओं के बारे में तर्क को कमजोर कर देगा?

a) प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश हमेशा आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता की उच्च दर का अनुभव करते हैं, जो संसाधन संपदा के स्पष्ट लाभों को प्रदर्शित करता है।

b) तकनीकी नवाचार संसाधन निष्कर्षण के पारिस्थितिक पदचिह्न को काफी कम कर सकते हैं।

c) "संसाधन अभिशाप" की घटना को मजबूत प्रशासन और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

d) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वैश्विक परिवर्तन मुख्य रूप से आर्थिक या राजनीतिक कारकों से बाधित है।

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

विकल्प a (प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश हमेशा आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता की उच्च दर का अनुभव करते हैं, जो संसाधन संपदा के स्पष्ट लाभों को प्रदर्शित करता है) एक ऐसे परिदृश्य को प्रस्तुत करके तर्क को चुनौती देता है जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता सीधे सकारात्मक आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से संबंधित है। यह "संसाधन अभिशाप" की चर्चा और संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के आसपास की जटिलताओं का खंडन करता है, यह सुझाव देता है कि प्राकृतिक संसाधनों की मात्र उपस्थिति परिच्छेद में उल्लिखित नकारात्मक परिणामों के बिना समृद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए, यह संसाधन संपदा के संभावित नुकसान के प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियों और शासन की आवश्यकता को नकार कर तर्क को कमजोर करता है।

Subject:) CSAT

Subtopic:) Reading Comprehension

WWW.PDFNOTES.CO